मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉण्डबैंड कमेटी (यू0पी0एस0बी0सी0) की दिनांक 13 मार्च, 2023 को सायं 6:30 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति- संलग्नानुसार

दूरसंचार विभाग द्वारा, दूरसंचार से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं तथा उन पर आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

2- मुख्य सचिव महोदय ने महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा जनपद-लखीमपुर खीरी तथा पीलीभीत के सीमावर्ती क्षेत्र के परिभ्रमण के बारे में उल्लेख करते हुए अवगत कराया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क/इन्टरनेट कनेक्टिविटी की भारी समस्या है। अतः बीएसएनएल/बीबीएनएल को निर्देश दिये गये कि सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर नेटवर्क/इन्टरनेट कनेक्टिविटी की समस्या को जल्द से जल्द दूर करें तथा समस्याओं का निदान करने में लगने वाले प्रस्तावित समय की विस्तृत आख्या/ समय-सारणी तत्काल शासन को उपलब्ध कराये। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त थानों, ब्लॉक, तहसील एवं सरकारी संस्थानों में नेटवर्क/इन्टरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाये, ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों में महिला एवं बालिका अपराध जैसे विषयों को ससमय दर्ज कर उनका निराकरण किया जा सकें।

(कार्यवाही-दूरसंचार विभाग)

3- दूरसंचार विभाग द्वारा Call Before u Dig(CBuD) ऐप के बारे में प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि CBuD ऐप का उद्घाटन मा0 प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2023 को किया जाना प्रस्तावित है। CBuD मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत की जाने वाली खुदाई के सम्बन्ध में विभागों के बीच परस्पर समन्वय स्थापित किया जाना है, जिससे अन्य भूमिगत इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्षति न पहुंचे। उक्त के क्रम में दूरसंचार विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा नोडल अधिकारी नामित कर CBuD ऐप पर लॉगिन आई0डी0 बना ली जाये। उ0प्र0 में अब तक राज्य स्तरीय नोडल तथा 04 राज्य स्तरीय विभागीय नोडल (नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति) एवं 140 अन्य लॉगिन बनाये जा चुके है।

इस सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुए कि सभी सम्बन्धित विभाग अपने विभाग के विभागीय नोडल अधिकारी नामित करते हुए सभी के लॉगिन बनवा लें। साथ ही शासन द्वारा एक शासनादेश निर्गत कर दिया जाये कि Excavation Agencies राज्य में कहीं भी खुदाई करने से पूर्व उसकी सूचना CBuD ऐप पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग)

4- भारत सरकार द्वारा निर्गत राइट ऑफ वे अमेन्डमेन्ट रूल दिनांक 17 अगस्त, 2022 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में हुई चर्चा में यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि इस विषय में वित्त विभाग का अभिमत प्रतीक्षित है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि

वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर शीघ्र अभिमत प्राप्त करते हुए, अन्य विभागों से प्राप्त अभिमत सहित एक बैठक करा लें।

(कार्यवाही- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

5- दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उ0प्र0 में इलेक्ट्रिक पोल्स के उपयोग हेतु शुल्क रू0 1700/- प्रति वर्ष है, जिस पर 10% की दर से वार्षिक वृद्धि की जाती है, जबकि भारत सरकार द्वारा निर्गत राइट आफ वे अमेन्डमेन्ट रूल दिनांक 17 अगस्त, 2022 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रति पोल रू0 300/- तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 150/- प्रति पोल प्रतिवर्ष निर्धारित है।

इस बारे में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि यू0पी0ई0आर0सी0 द्वारा परिवर्तित दरें कुछ दिन पूर्व निर्गत की गयी हैं, जोकि भारत सरकार के राइट आफ वे अमेन्डमेन्ट रूल दिनांक 17 अगस्त, 2022 में उल्लिखित दरों से काफी भिन्न है। परन्तु यदि राज्य सरकार राइट आफ वे अमेन्डमेन्ट रूल दिनांक 17 अगस्त, 2022 को अंगीकृत किया जाता है तो उसमें निर्धारित दरें स्वीकार कर ली जायेंगी।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि राज्य में नेटवर्क/इन्टरनेट कनेक्टिविटी तथा निवेश को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिगत राइट आफ वे अमेन्डमेन्ट रूल दिनांक 17 अगस्त, 2022 को अंगीकृत किये जाने के की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जायें।

(कार्यवाही-ऊर्जा विभाग)

6- 5G रोल आउट के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि 5G Technologies Training/ Workshop शीघ्र करा ली जाये। इसमें प्रदेश सरकार के विभागों एवं सम्बन्धित हितधारकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायें एवं उन्हें 5G रोल आउट के विषय पर अवगत कराया जायें।

(कार्यवाही- दूरसंचार तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

7- दूरसंचार विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत OM No. 2-10/2022-Policy Dt-26.10.2022 का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि मोबाइल टॉवर की अवस्थापना सम्बन्धी जो आवेदन किसी कारणवश यदि निरस्त हो जाते हैं, तो उन्हें उसी साइट हेतु पुनः आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क रू0 10,000/- की छूट प्रदान की जाये।

इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि State Broadband Committee (SBC) द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2022 में लिये गये पूर्व निर्णय के अनुसार रू0 10,000/- प्रोसेसिंग शुल्क है, अतः इसे समायोजित नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुए कि मोबाइल टॉवर स्थापना के लिए प्राप्त आवेदन के सापेक्ष (आवेदन निरस्त होने की स्थति में), प्रति आवेदन एक अतिरिक्त अवसर प्रदान कर दिया जाये। यह व्यवस्था नवीन प्राप्त होने वाले मोबाइल टावर सम्बन्धी आवेदनों पर लागू होगी।

(कार्यवाही- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

8- नेशनल बिल्डिंग कोड तथा मॉडल बिल्डिंग बाई लॉज पर हुई चर्चा के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नेशनल बिल्डिंग कोड तथा मॉडल बिल्डिंग

बाईलॉज के अनुसार संशोधन किये जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है, जो कि शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

(कार्यवाही- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

9- दूरसंचार विभाग द्वारा नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों/नगर निगमों द्वारा पॉलिसी में निर्धारित शुल्क रू0 10,000/- के अतिरिक्त धनराशि की भी मांग की जा रही है। इसके अलावा कुछ जनपदों में टॉवर्स को सील भी किया जा रहा है तथा इसके अतिरिक्त वन विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे है।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि दूरसंचार विभाग ऐसी समस्याओं का एक संक्षिप्त विवरण तैयार कर शासन को उपलब्ध करा दे, जिसके आधार पर राइट आफ वे अमेन्डमेन्ट रूल दिनांक 17 अगस्त, 2022 को अंगीकृत किये जाने के पश्चात सम्बन्धित विभागों को अपने-अपने विभागों में पृथक रूप से शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

इस सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन को निर्देश प्राप्त हुए कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए दूरसंचार सम्बन्धी समस्याओं के निदान हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठकें करवा दें। मोबाइल टॉवर्स को सील न किये जाने हेतु निर्गत आदेश को पुनः प्रसारित कर दें।

वन विभाग से सम्बन्धी समस्याओं हेतु निर्देश प्राप्त हुए कि दूरसंचार विभाग वन विभाग से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निदान करवा लें। वर्तमान में वन विभाग द्वारा संचालित परिवेश पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जा रहा है।

(कार्यवाही- दूरसंचार तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग)

10- कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सम्बन्धी बिन्दु पर चर्चा में प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में पूर्व में विभागीय अधिकारियों तथा टी0एस0पी0/आई0पी0 के बीच चर्चा की जा चुकी है तथा यह व्यवस्था लागू किये जाने की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है।

(कार्यवाही- ऊर्जा विभाग)

11- दूरसंचार विभाग द्वारा भारतनेट, भारतनेट फेस-1, भारतनेट फेस-2 बीटीएस कवरेज स्टेटस ऑफ विलेज प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। इस सम्बन्ध में पाया गया कि प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट अपूर्ण है। अतः निर्देश दिये गये कि दूरसंचार विभाग/बीबीएनएल तुलनात्मक विवरण शासन को उपलब्ध कराये।

(कार्यवाही- दूरसंचार विभाग)

12- Digital Infrastructure Providers Association (डी0आई0पी0ए0) द्वारा अनुरोध किया गया कि नोएडा तथा गाजियाबाद के जनपदों में अतिरिक्त रूप से धनराशि की मांग किये जाने की समस्यायें आ रही है। इस क्रम में मुख्य सचिव महोदय, द्वारा यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिये गये कि इस प्रकार की समस्याओं के निस्तारण हेतु जनपदों की बैठक अलग से करा ले।

(कार्यवाही- यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड)

13- Digital Infrastructure Providers Association (डी0आई0पी0ए0) द्वारा अवगत कराया गया कि निवेश मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर एक आई0डी0 के माध्यम से अधिकतम 99 आवेदन ही किये जा पा रहे है। इस क्रम में यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में उ0प्र0 के राइट ऑफ वे पोर्टल पर निवेश मित्र तथा सुगम संचार के माध्यम से आवेदन प्राप्त हो रहे है। सुगम संचार पर इस तरह की बाध्यता नहीं है, परन्तु निवेश मित्र पोर्टल पर एक आई0डी0 से अधिकतम 99 आवेदन ही किये जाने की बाध्यता है। इस सम्बन्ध में निवेश मित्र को पूर्व में अवगत कराया जा चुका है।

इस सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुए कि निवेश मित्र से समन्वय स्थापित कर निस्तारण करवा लें।

(कार्यवाही- निवेश मित्र)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

अक्षय त्रिपाठी
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या:-508/78-1-2023-666/2020

लखनऊ: दिनांक: 02 मई, 2023

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
नगर विकास विभाग/लोक निर्माण विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/ परिवहन विभाग/
पंचायती राज विभाग/ औद्योगिक विकास विभाग एवं सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।
3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4- राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन निदेशक, दूरसंचार विभाग।
5- सलाहकार/ Sr DDG of Dot of The UP (East)& UP (West) LSAs
6- CGM, BSNL UP (East) and UP (West), Telecom Circles
7- CGM BBNL - State Head UP (East) & UP (West)
8- COAI / DIPA
9- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
11- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
13- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
संयुक्त सचिव।

उ0प्र0 स्टेट ब्रॉडबैण्ड कमेटी (यू0पी0एस0बी0सी0) की मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13-03-2023 को सायं 6:30 बजे से 7:00 बजे तक लोक भवन, प्रथम तल स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत बैठक में उपस्थित अधिकारीगण:-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0/ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1	R K M SRIVASTAVA	Additional DG (T)	Dept-of Telecom.	9471008685	
2	Ajay Chauhan	PS, PWD.	PWD	8795810001	
3	A. K. Mishra.	DDG	DOT.	9415011900	
4	Rakesh Kumar	DDG	DoT	9868217061	
5	रंजन कुमार	सचिव	नगर विकास		
6	Parmatma Rai	Director	DOT	9868136843	
7	Prabhu N. Singh	Secretary	Revenue	—	
8	Rajamouli	Secretary	Home	9454415002	
9	Salil Kumar	GM NWO-CFA	BSNL	9450701786	
10	Pramod Yadav	GM(NOFN)	BSNL	9435713599	
11	Abhinav Kr. Verma	DGM Mobile planning BSNL	BSNL	9412000529	
12	सुधीन्द्र कुमार	विशेष सचिव	ग्राम्य विकास	9454412460	
13	अवधेश कुमार खरे	संयुक्त सचिव	पंचायतीराज	9454413707	

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0/ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
14	J.P. Maurya	E.E	U.P. Pollution Control Board	979176310	[signature]
15	Shahab Rashid Khan	SP/AD	Police Technical Services	9454400349	[signature]
16	Rakesh Kr Mishra	Spl Sec	Housing	9454577144	[signature]
17	Pramod Kumar Pandey	OSD BoR	Revenue	8707428534	[signature]
18	Gangotri Kumar Dubey	OSD U.P. Van Nigam	Forest	9997676903	[signature]
19	Pramod Kumar Dubey	CCF PAAL	Efce	7839435035	[signature]
20	PANKAJ KUMAR	MD UP POWER CORP	ऊर्जा	7380388884	[signature]
21	Akshay Tripathi	SS IT&E	IT & E	7897866772	[signature]
22					
23					
24					
25					
26					

उ0प्र0 स्टेट ब्रॉडबैण्ड कमेटी (यू0पी0एस0बी0सी0) की मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13-03-2023 को सायं 6:30 बजे से 7:00 बजे तक लोक भवन, प्रथम तल स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत बैठक में उपस्थित अधिकारीगण:-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0/ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1	R K M SRIVASTAVA	Additional DG (T)	Dept. of Telecom.	9471008685	[signature]
2	Ajay Chauhan	PS, PWD.	PWD	8795810001	[signature]
3	A. K. Mishra.	DDG	DoT.	9415011900	[signature]
4	Rakesh Kumar	DDG	DoT	9868217061	[signature]
5	रंजन कुमार	सचिव	नगर विकास		[signature]
6	Parmatma Rai	Director	DOT	9868136843	[signature]
7	Prabhu N. Singh	Secretary	Revenue	—	[signature]
8	Rajamouli	Secretary	Home	9454415002	[signature]
9	Salil Kumar	GM NWO-CFA	BSNL	9450701786	[signature]
10	Pramod Yadav	GM(NOFN)	BSNL	9435713544	[signature]
11	Abhinav Kr. Verma	DGM Mobile planning BSNL	BSNL	9412000529	[signature]
12	सुधीन्द्र कुमार	विशेष सचिव	ग्राम्य विकास	9454412460	[signature]
13	अवधेश कुमार खरे	संयुक्त सचिव	पंचायतीराज	945441317	[signature]

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0/ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
14	J.P. Maurya	E E	U.P. Pollution Control Board	979476310	
15	Shahab Rashid Khan	SP/AD	Police Technical Services	9454400349	
16	Rakesh Kr Mishra	Spl Sec	Housing	9454577744	
17	Pramod Kumar Pandey	OSD BOR	Revenue	8707428534	
18	Gangotri Kumar Dubey	OSD U.P Van Nigam	Forest	9997676903	
19	Pramod Kumar Dubey	CCF PADL	EFCC	7839435035	
20	PANKAJ KUMAR	MD UP POWER CORP	ऊर्जा	7380388884	
21	Akhilanj Tripathi	SS IT & E	IT & E	7897866772	
22					
23					
24					
25					
26					